राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड

85वीं बैठक दिनांक 27 जुलाई, 2023 की कार्य सूची (एजेण्डा)

एजेण्डा संख्या – 1	84वीं बैठक दिनांक 28.03.23 के कार्य बिंदुओं से संबंधित कृत कार्यवाही की रिपोर्ट (ATR)
एजेण्डा संख्या – 2	84वीं बैठक के कार्य बिंदुओं की पुष्टि
एजेण्डा संख्या – 3	(क) वार्षिक ऋण योजना 2023–24 (ख) वार्षिक ऋण योजना 2022–23 एवं प्राथमिक क्षेत्र में ऋण उपलब्धि
एजेण्डा संख्या – 4	नाबार्ड का एजेण्डा
एजेण्डा संख्या – 5	रोजगार सृजन ऋण योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट
एजेण्डा संख्या – 6	(क) एन.पी.ए. की समीक्षा (ख) लम्बित वसूली प्रमाणपत्र (R.C.)
एजेण्डा संख्या – 7	(i) वित्तीय समावेषन : (क) बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एवं कैपेसिटी बिल्डिंग (ख) बैंकिंग सुविधा से अनाच्छादित गांव (ग) सामाजिक सुरक्षा योजना (घ) जन सुरक्षा योजनाओं हेतु संतृप्तता अभियान (ङ) वित्तीय साक्षरता हेतु केन्द (CFL) (च) वित्तीय साक्षरता केन्द्र (FLC) (ii) Fintech Absorption (iii) Depositors Education and Awareness (DEA)
एजेण्डा संख्या – 8	ऋण जमा अनुपात
एजेण्डा संख्या – 9	ऋण आवेदन पत्रों के Rejected/ Returned के कारण
एजेण्डा संख्या – 10	एम.एस.एम.ई.
एजेण्डा संख्या – 11	(क) मै. रुद्रा ऑटोटैक इंजीनियरिंग प्रा. लि. पंतनगर **एवं** मै. नैनी ऑटो टैक रुद्रपुर यू.एस. नगर : दि नैनीताल बैंक लि0 द्वारा प्रस्तुति (ख) मै. गुरुकृपा इंटरप्राईजेज : पंजाब नेषनल बैंक द्वारा प्रस्तुति
एजेण्डा संख्या – 12	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड

85वीं बैठक दिनांक 27 जुलाई, 2023 की कार्य सूची (एजेण्डा)

एजेण्डा संख्या – 1 :

(क) 84वीं बैठक दिनांक 28.03.23 के कार्य बिंदुओं से संबंधित कृत कार्यवाही की रिपोर्ट (ATR) :

क्र	कार्य बिंदु	कृत कार्यवाही
1.	**षासन से संबंधित कार्य बिंदु** (क) स्वामित्व कार्ड विषयक निम्नानुसार षासनादेष षासन से अपेक्षित है : a. Legal recognition of SVAMITVA card under State Land Revenue Act. b. Provision for noting of Charge/Mortgage/ Attachment on the property will be made. c. Modalities for creation of mortgage/noting of charge on SVAMITVA card treating these as Title of Property. **(कार्यवाही : राजस्व विभाग)**	**(क)** – सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड षासन की अध्यक्षता में स्वामित्व कार्ड विषयक बैठक दिनांक 21.06.2023 को सचिवालय में आयोजित की गयी। बैठक में अपर सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड षासन, सहायक महाप्रबन्धक, एस. एल.बी.सी., भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेषनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंक के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभागिता की गयी। – राजस्व अनुभाग–1, उत्तराखण्ड षासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 689/XVIII/2019-07(21)/2016 दिनांक 31.10.2019 के क्र.सं. 8 एवं 9 में कार्य बिंदु का a, b & c point पूर्ण हो रहे है। – पंचायत राज विभाग वित्तीय सेवायें विभाग से उक्त विषयक वार्ता कर, वित्तीय सेवायें विभाग द्वारा समस्त बैंकों के कार्पोरेट कार्यालय को उक्त विषयक दिषानिर्देष जारी करने की अपेक्षा है।
	(ख) ऋण–जमा अनुपात में बृद्वि के लिए कार्य योजना (Action Plan) बनाये जाने हेतु राज्य स्तर पर उप–समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है। **(कार्यवाही : वित्त विभाग)**	**(ख)** राज्य स्तर पर उप–समिति का गठन किया गया है। सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड षासन की अध्यक्षता में दिनांक 21.06.2023 को आयोजित उप–समिति की बैठक में सचिव कृषि, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, एस.एल.बी.सी., भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेषनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंक के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभागिता की गयी। – बैठक में सचिव, कृषि द्वारा अवगत कराया गया कि जिला उत्तरकाषी, पिथौरागढ़, नैनीताल एवं यू.एस. नगर का ऋण–जमा अनुपात ठीक है तथा जिला बागेष्वर एवं रुद्रप्रयाग का ऋण–जमा अनुपात बहुत कम है।
	(ग) विभिन्न ऋण योजनाओं अंतर्गत निरस्त किये गये ऋण आवेदन पत्रों के कारणों की समीक्षा हेतु एक उप–समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है। **(कार्यवाही : वित्त विभाग)**	**(ग)** निरस्त किये गये ऋण आवेदन पत्रों के कारणों की समीक्षा हेतु गठित उप–समिति की बैठक दिनांक 12.04.2023 को सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड षासन की अध्यक्षता में आयोजित की गयी थी। बैठक के कार्यवृत्त समस्त बैंकों को प्रेषित कर दिये गये हैं।

2.	**एस.एल.बी.सी. से संबंधित कार्य बिंदु :** अनाच्छादित 103 गांवों में बैंक षाखा खोलने हेतु आवष्यक सेवाओं की अनुपलब्धता वर्णित कर, सूची षासन को प्रेषित करें ।	अंतर–राज्य परिषद सचिवालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्रांक D.O. No. 5/1/2021-ZCS(C) दिनांक 28.08.2022 के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य में अनाच्छादित 103 गांवों को बैंकिंग सुविधा से आच्छादित करने हेतु, जिला सहकारी बैंक एवं आई.पी.पी.बी. को निर्देषित किया गया है। अनाच्छादित 103 गांवों में से 10 गांव बैंक से तथा 37 गांव आई.पी.पी.बी. से कबर है, अवषेष 56 गांवों में से 11 गांवों में आई.पी.पी.बी. द्वारा बैंकिंग सुविधा प्रदान किये जाने हेतु, पोस्ट ऑफिस को बैंक में परिवर्तन करने का कार्य प्रगतिषील है। अवषेष 44 गांवों में स्थिति निम्नवत है : 1. 17 गांवों में विद्युत सेवा नही है। 2. 39 गांवों में टेलीकॉम कनेक्टिविटी नही है। 3. 12 गांवों में आबादी प्रवासी है। 4. 11 गांवों में सड़क नही है।

<u>एजेण्डा संख्या – 2</u> :

<u>84वीं बैठक के कार्य बिंदुओं की पुष्टि</u> :

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड की 84वीं बैठक, दिनांक 28 मार्च, 2023 के कार्य बिंदुओं पर संबंधित विभागों एवं बैंकों द्वारा की गयी कार्यवाही से राज्य स्तरीय बैकर्स समिति, उत्तराखण्ड को अवगत कराया गया है, जिसकी पुष्टि निम्नलिखित उप–समितियों की बैठक में सभी सदस्यों की सहमति से मान लिया गया है।

उप–समितियों की बैठकों के आयोजन का विवरण निम्नवत है :

1. समाज कल्याण बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21 जून, 2023

प्रमुख विन्दु –

- सम्बन्धित विभाग एस.एल.बी.सी. को NULM-2 तथा PM AJAY के पोर्टल की जानकारी प्रदान करेंगे।

2. ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक दिनांक 30 जून, 2023

प्रमुख विन्दु –

- PMFME योजना अंतर्गत Rejected/Returned ऋण आवेदन पत्रों का विभाग review करेंगे तथा सम्बन्धित कारणों से अवगत करायेंगे।

3. अवस्थापना विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक दिनांक 30 जून, 2023

प्रमुख विन्दु –

- PM SVANidhi योजना अंतर्गत 90 दिन से अधिक लम्बित ऋण आवेदन पत्र, ULB के सहयोग से बैंक षीघ्र निष्पादित करेंगे तथा विभाग Tranche – 1 में समुचित संख्या में ऋण आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित करेंगे।
- PM SVANidhi योजना अंतर्गत Rejected / Returned ऋण आवेदन पत्रों का विभाग review करेंगे तथा सम्बन्धित कारणों से अवगत करायेंगे।

4. Deepening of Digital Payments / Financial Inclusion / New Branch Opening हेतु गठित राज्य स्तरीय उप–समिति की बैठक दिनांक 12 जून, 2023

प्रमुख विन्दु –

- बैंकिंग सेवाओं से 39 अनाच्छादित गांवों में टेलीकॉम विभाग, टेलीकॉम कनेक्टिविटी की समीक्षा करेंगे तथा टेलीकॉम कनेक्टिविटी से जोड़ने का कार्य करेंगे।

5. Steering Sub-Committee की बैठक दिनांक 04 जुलाई, 2023

एजेण्डा संख्या – 3 :

(क) वार्षिक ऋण योजना 2023–24 :

राज्य के समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धकों से वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु प्राप्त वार्षिक ऋण योजना को भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा समीक्षा उपरांत क्षेत्रवार/सेक्टरवार लक्ष्य आवंटित किये गये हैं, जो कि सदन के अनुमोदन हेतु निम्नवत प्रस्तुत है :

(Amt. in Cr.)

Target	Crop Loan	Term Loan (Including Agr. Infrastructure & Ancillary Activities)	Farm Sector (Agriculture)	Non Farm Sector (MSME)	Other Priority Sector	Total Priority Sector
	A	B	(A+B) = C	D	E	(C+D+E) = F
ACP 2023-24	7646.00	5500.31	13146.31	16500.00	4286.94	33933.25
ACP 2022-23	7334.38	5216.68	12551.06	11994.15	4115.16	28660.37
Difference	**311.62**	**283.63**	**595.25**	**4505.85**	**171.78**	**5272.88**
Increase %	**4.25%**	**5.44%**	**4.74%**	**37.57%**	**4.17%**	**18.40%**

वित्तीय वर्ष 2022–23 की वार्षिक ऋण योजना **रु. 28660.37** करोड़ में **रु. 5272.88 करोड़ (18.40%)** की बृद्वि कर वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु वार्षिक ऋण योजना **रु. 33933.25 करोड़** की गयी है।

बिगत 5 वर्षो में वार्षिक ऋण योजना अंतर्गत प्राप्त लक्ष्य एवं राज्य में ऋण सम्भाव्यता को मध्यनजर रखते हुये वार्षिक ऋण योजना 2023–24 तैयार की गयी है।

(ख) वार्षिक ऋण योजना 2022–23 एवं प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण उपलब्धि :

बिगत 3 वर्षो की वार्षिक ऋण योजना एवं प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण उपलब्धि :

(Amt. in Cr.)

F.Y.	Crop Loan			Term Loan			Farm Sector			Non Farm Sector (MSME)			Other Priority Sector			Total PSA		
	Target	Achievement	% age	Target	Achievement	% age	Target	Achievement	% age	Target	Achievement	% age	Target	Achievement	% age	Target	Achievement	% age
2022-23	7334	5649	**77**	5217	4704	**90**	12551	10353	**82**	11994	15911	**133**	4115	4160	101	28660	30424	**106**
2021-22	7181	5208	**73**	5118	3631	**71**	12298	8839	**72**	10454	10055	**96**	3859	2378	**62**	26611	21272	**80**
2020-21	7952	4098	**52**	5271	2396	**45**	13222	6493	**49**	8851	8624	**97**	3721	1177	**32**	25794	16294	**63**

बिगत 3 वर्षो में राज्य में प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण उपलब्धि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मापदण्डों से अधिक है।

एजेण्डा संख्या – 4 :

(i) NABARD Agenda :

1. Financial Inclusion :

NABARD has sanctioned an amount of ₹9.50 crore during FY 2022-23 as grant support to various banks for various financial inclusion initiatives viz: NukkadNataks, Financial and Digital (FiDGi)Literacy camps, Handheld projectors, Positive Pay System, micro-ATM deployment, examination fees of BC/BF and Phase II CFLs. In spite of awareness among all stakeholders, only ₹2.13 crore could be released during the year as against ₹4.61 crore during 2021-22.Banks need to increase the off-take of FIF in their area of operation.

2. Social Security Schemes :

Keeping in mind the huge gap in eligible operative PMJDY account holders and enrolment under Social Security Schemes (PMSBY, PMJJBY & APY) in the state, banks may focus on more coverage.

3. Upscaling of Centre for Financial Literacy (CFL) :

₹6.24crore have been sanctioned for 16 CFLs under Phase II for grant support under Financial Inclusion Fund (FIF). Banks concerned - SBI, BoB and PNB – may submit the claims at the earliest.

4. Agriculture infrastructure Fund (AIF) :

An allocation of ₹ 785 crore has been made to Uttarakhand State under the scheme for a period of 4 years from 2020-21 to 2023-24.This scheme provides a medium to long term debt financing facility for investment in viable projects for post-harvest management infrastructure and community farming through interest subvention and financial support. All loans under this scheme are eligible for interest subvention of 3% p.a. up to a loan limit of ₹2.oo crore. This subvention will be available for a maximum period of 7 years. The proposed duration of this scheme is 2020-21 to 2032-33. Further, credit guarantee fee is being borne by Govt. of India on behalf of loans disbursed by lending Institutions under the scheme.The main reasons for pendency/ rejection listed by banks are as under:

- DPR is incomplete or activities are not eligible under the scheme.
- Land is already mortgaged for another loan while as per bank circulars the land should be exclusively mortgaged to this project only.
- Incomplete details of the promoter, about activity, non-submission of required documents/ details by promoters, etc.

5. KCC saturation and KCC to Animal Husbandry (AH) and fisheries farmers :

Govt. of India had launched a special drive on 08.02.2020 to cover all PM KISAN beneficiaries under the fold of KCC Scheme. Further, in June 2020, a special campaign was launched to cover 2.50 crore Animal Husbandry farmers under the fold of KCC. NABARD was assigned a prominent role in coordinating with RRBs and RCBs on a regular basis to ensure a successful campaign. As a result of continuous campaign by banks, the coverage has improved and status in the State as on 05.06.2023 is as under:

Crop Loan				
Bank	Applications Received	Applications sanctioned	Limit sanctioned (in ₹ crore)	Pending applications
Cooperatives	29683	29683	253.54	0
RRB	15914	9898	89.28	0
Animal Husbandry (Dairy, Fisheries, Poultry & Others)				
Bank	Applications Received	Applications sanctioned	Limit sanctioned (in ₹crore)	Pending applications
Cooperatives	22276	19322	116.28	0
RRB	7284	3818	23.87	0

6. Capital linked Credit Subsidy Schemes :

- **Agri-clinic and Agribusiness Centers Scheme (ACABC):** ACABC scheme is being implemented by MoA& FW, GoI with NABARD acting as subsidy channelizing agency. The objectives of the scheme are to supplement efforts of public extension by providing extension and other services to farmers, to support agricultural development and create gainful self-employment opportunities to unemployed agricultural graduates etc. The scheme is operational for 2023-24. Banks may finance the eligible borrowers and submit the claims to NABARD.
- Pending refunds of a total of ₹2.099 crore under GoI schemes, viz., PVCF and DPVCF - Interest Free Loans provided to Banks by NABARD in Uttarakhand. The undernoted banks may please initiate refunds immediately to NABARD, so that same could be refunded to GoI. The matter has been taken up by NABARD RO separately with Banks along with reminder. Bank wise details given below:
  i. BOB: ₹1,02,16,974/-
  ii. SBI: ₹72,79,830/-
  iii. Union Bank of India: ₹16,30,085/-

iv. PNB: ₹8,73,550/- (₹7,33,550/- for Zonal Office Dehradun and ₹1,40,000/- for ZO Agra)
v. Indian Bank: ₹7,92,200/-
vi. CBI: ₹1,54,100/-
vii. UGB: ₹51,464/-

- New AMI Scheme-Scheme is extended till 31.03.2026

7. Credit Guarantee Funds

- **CSS-FPO -** In order to ensure easy access& accelerate flow of institutional credit to FPOs at comparative rate from mainstream Banks and Financial Institutions, a dedicated Credit Guarantee Fund (CGF) has been created in NABARD, being maintained by NABSanrakshan Trustee Co. Pvt. Ltd., a dedicated trust floated by NABARD. Details of credit guarantee cover are as under:

Sr. No.	Loan Upto	Credit Guarantee	Guarantee Fee
1	Upto₹ 1.00 crore	85%	0.75%
2	Above ₹1.00crore – upto₹2.00crore	75%	0.85%

The credit guarantee cover will be limited to the project loan of ₹2 crore (per FPO). In case of default, claims shall be settled up to 85% or 75 % of the amount in default subject to maximum cover as specified above. The Cover shall only be granted after the Eligible Lending Institute (ELI) enters into an agreement with NABARD and shall be granted or delivered in accordance with the Terms and Conditions decided upon by NABARD from time to time.

The Eligible Lending Institute (ELI) shall pay the Guarantee Fee upfront to NABARD within 30 days from the date of issue of sanction letter for CGC.

8. Farm Sector Development:

- **Credit access to the FPOs**: NABARD has promoted 133 FPOs in the state; however, only 64 have been credit linked till date. Banks may direct their branches to extend their support in providing loans/ CC limits to the eligible FPOs (50 of these FPOs are almost 05 years old and mature enough to absorb credit support from Financial Institutes). Credit guarantee cover available for all FPOs dealing with agriculture, horticulture and bee keeping through NAB Sanrakshan Trustee Pvt. Ltd. can be availed by banks thereby further reducing their risks.
- Progress under CSS- FPOs in the state as on 31.03.2023 are as under :

Sr.	Particulars	NABARD	NAFED	NCDC	NDDB	SFAC	TRIFED	UOCB	Total
1	FPOs Allocated (No. of FPOs)	31	31	26	2	51	2	11	**154**
2	Registration (No. of FPOs)	31	21	26	1	36	2	0	**117**
3	No. of shareholders	6152	1192	5662	7	2326	506	0	**15845**
4	Bank linkage-SB A/c opened (No. of FPOs)	31	8	25	1	25	1	0	**91**

- **WDF/Springshed/ IWMS/ TDF-**

NABARD has been implementing 05 watershed development projects &10Springshed development projects spreading over10,074 ha in the state. 05 tribal development projects (TDP) are ongoing in the state. Besides, 02 JIVA projects for promotion of natural farming through agro-ecological approach are being implemented, in completed Watershed (Pauri) and TDP (Dehradun) projects of NABARD.

9. Off Farm Sector Development :

(a) Rural Haat- The eligible agency can submit proposal for grants assistance under Rural Haat scheme of NABARD.State Govt. / district administrationcan make a provision for space allocation for Rural Haats where weekly markets are functional. Potential areas for marketing of products could also be identified at district administration level.

(b) Skill Development- NABARD supports skill development programmes through RSETIs (sponsored by Banks) and other reputed Institutes. RSETIs/ Banks can approach NABARD to avail financial support for training being conducted by them.

10. Micro Finance

- **SHG- Bank Linkage Programme:** As per NRLM data available on the website there are 54,201 SHGs or 4,03,868 women who are associated with SHG movement in the State. However, as per NABARD's report on Status of Micro Finance in India – 2021-22 (as on 31.03.2022) only 21,552 SHGs had bank loan outstanding of ₹134.24 crore in the State. It indicates huge gap in SHG financing. Banks need to bridge this gap.
- **Formation of JLGs:** NABARD currently provides a promotional grant assistance to banks for promotion of JLGs. Banks may explore the possibility of entering into aMoU with NABARD for promotion of JLGs.
- **Village Level programmes (VLPs):** To boost the financial inclusion awareness, popularize various govt. schemes, increase bankers- SHGs interface and further strengthen the SHG- BLP, NABARD extends financial support for conducting VLPs through branches of Commercial Banks, RRBs and Co- operative banks across all the 13 districts of the State. NABARD will reimburse ₹2000 per VLP for the purpose.All banks are requested to issue necessary instructions to their branches to take advantage of VLPs forcreating awareness on SHG- BLP, financial literacy and promotion of other products.

  The progress on conduct of VLPs may be incorporate as a regular agenda in BLBC/ DCC/ DLRC Meetings.

11. International Year of Millets (IYM- 2023): The UN General Assembly has declared the year 2023 'International Year of Millets'. It will help in creating awareness throughout the world about the significant role of millets in significant role of millets in sustainable agriculture and its benefits as a smart and superfood.

IYM 2023 aims to contribute to the UN 2030 Agenda for different SDGs (Zero hunger, good health &well-being, decent work & economic growth, responsible consumption & production, climate action and life on land). India is poised to become the global hub for millets with a production of more than 170 lakh tonnes which makes for more than 80% of the millets produced in Asia (*source PIB & FAO*).Finger millet (Ragi), barnyard millet (Jhangora), foxtail millet and proso millets and pulses have a great potential to withstand stress condition as compared to other crops in the State.

Various initiatives have been taken by Govt. of Uttarakhand to promote millets in the State. As per data provided by the Directorate of Millets Development, Jaipur for the year 2021-22; Uttarakhand has grown RAGI in the area of 0.86 lakh ha, having production of 1.27 lakh tonnes with the yield of 1478 Kg/ha (more than the all India average of 1401 Kg/ ha). Further, Uttarakhand has produced 0.73 lakh tonnes of Small Millets in the area of 0.47 lakh ha, having yield of 1559 Kg/ha (above national average of 885 Kg/ ha).

While millets are gaining popularity among consumers, the actual consumption is not increasing, and supply cannot match it if large sections start consuming millets. Hence, we need two-pronged strategies to manage supply and demand side issues.

(ii) इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य गोदाम रसीद :
Electronic Negotiable Warehouse Receipts (e-NWR) :

देश में नेगोषिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट प्रणाली किसानों को अपने खेतों के पास गोदामों में सुरक्षित और वैज्ञानिक भंडारण और संरक्षण के लिए अपनी उपज को स्टोर करने और अपने स्टॉक जमा करने के एवज में जारी किए गए नए NWR के लिए बैंकों से गिरवी ऋण लेने में सक्षम बनाती है। इसलिए NWR किसानों को पीक मार्केटिंग सीजन के दौरान कृषि उपज की संकटपूर्ण बिक्री से बचने और कटाई के बाद के भंडारण के नुकसान से बचने में सहायता करता है।

वेयरहाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA), भारत सरकार वेयरहाउसिंग (डेवलपमेंट एंड रेगुलेषन) एक्ट, 2007 के प्रावधानों के अनुसार NDR का कार्यान्वयन सुनिष्चित करती है।

e-NWR की विषेषतायें निम्नवत हैं :

- e-NWR केवल इलेक्ट्रॉनिक रुप में उपलब्ध है।
- e-NWR के लिए सूचना का एकमात्र स्रोत रिपॉजिटरी होगा।
- e-NWR की जानकारी की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता रिपॉजिटरी द्वारा प्रदान की जाएगी।
- एक e-NWR की एक समय वैधता होती है, जो कमोडिटी के षेल्फ–लाइफ के साथ को–टर्मिनस होती है या वेयरहाउस से पूरी तरह से कमोडिटी की वापसी होती है, जिसके बाद यह समाप्त हो जाती है।
- एक e-NWR को कुछ षर्तो के तहत नीलाम किया जा सकता है। जैसे कि ऋण चुकाया नही गया है, समाप्ति पर डिलीवरी नहीं ली गई है और गोदाम में वस्तु की क्षति या खराब होने पर।
- सभी e-NWR का ऑफ–मार्केट या ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म/एक्सचेंजों के माध्यम से कारोबार किया जा सकता है।
- e-NWR एक बार लेन–देन के साथ दर्ज हो जाने के बाद, चाहे वह प्रतिज्ञा हो या हस्तांतरण या निकासी, किसी अन्य उद्देष्य के लिए एक साथ उपयोग नही किया जा सकता है। इस प्रकार एक ही e-NWR का दोहरा उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

एजेण्डा संख्या – 5 :

रोजगार सृजन ऋण योजनाओं की प्रगति :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं की प्रगति (F.Y. 2022-23) :

Scheme		Annex.	Target	Received	Sanctioned	Disbursed		% of Disbursement	Returned	Pending
			No.	No.	No.	No.	Amt. (In Cr.)	%	No.	No.
SCP	*SC	1	886	989	648	632	4.30	71	90	251
	ST	2	100	106	72	70	0.30	70	6	28
	Minority	3	120	182	100	100	1.17	83	82	0
	Total	4	1106	1277	820	802	5.77	73	178	279
NULM		5	1000	1235	1154	1139	---	114	---	---
NRLM		6	18000	25174	---	19609	181.38	109	---	---
PM SVANidhi		7	25000	27785	18666	17660	---	71	7786	1006
Stand-up India		8	2174	313	313	313	55.37	14	---	---
MUDRA		9	Rs. 2500 Cr.	---	---	307268	3583.20	143	---	---
PMEGP		10	1783	5021	2453	1850	124.11	104	2184	384
				Margin Money Target : Rs. 51.71 Cr. **Margin Money Claimed :** Rs.53.57 Cr**. (104%)**						

- *SCP - SC योजना के स्थान पर PM AJAY योजना प्रारम्भ की जानी है, जिसमें एस.सी. वर्ग के आवेदकों को एस.एच.जी. ग्रुप में वित्तपोषित किया जाना है।
- एन.यू.एल.एम. – 2 योजना प्रारम्भ की जानी है। एन.यू.एल.एम. योजना अंतर्गत बैंकों में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों को दिनांक 30.09.2023 तक निष्पादित किया जा सकता हैं।
- अग्रणी जिला प्रबन्धक, निजी बैंकों को भी सरकार प्रायोजित ऋण योजना अंतर्गत लक्ष्य आवंटित करें तथा डी.एल.आर.सी. बैठक में प्रगति विषयक चर्चा करें।

(ख) राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं की प्रगति (F.Y. 2022-23) :

Scheme		Annex.	Target	Received	Sanctioned	Disbursed		% of Disbursement	Returned /Rejected	Pending
			No.	No.	No.	No.	Amt. (In Cr.)	%	No.	No.
VCSGSY	Vehicle	11	150	283	199	193	**22.86**	129	66	18
	Non Vehicle	12	100	190	89	86	**31.66**	86	61	40
Home Stay		13	200	452	207	207	**47.43**	104	172	73
MSY		14	6000	22084	9015	7262	--	121	10190	2879
MSY – NANO		15	10000	7050	3168	2241	--	22	2754	1128

- समबन्धित विभागों से आग्रह है कि वे योजना अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य से दोगुना ऋण आवेदन पत्र बैंक षाखाओं को प्रेषित करें।
- बैंकों से आग्रह है कि वे विगत वर्ष के लम्बित ऋण आवेदन पत्र विभाग को वापस ना करें तथा उनका निस्तारण करें।
- अग्रणी जिला प्रबन्धक, निजी बैंकों को भी सरकार प्रायोजित ऋण योजना अंतर्गत लक्ष्य आवंटित करें तथा डी.एल.आर.सी. बैठक में प्रगति विषयक चर्चा करें।

एजेण्डा संख्या – 6 :

(क) एन.पी.ए. :

As on 31st March, 2023 **(Amt. in Cr.)**

S. No.	NAME OF SCHEME	Total Outstanding		Gross NPA		Gross NPA%
		No.	Amount	No.	Amount	Amount
1	PMEGP	6907	199.57	887	19.76	**9.90**
2	NULM	4003	35.38	712	5.19	**14.67**
3	NRLM	21250	116.14	944	5.75	**4.95**
4	MSME	237056	21521.59	39554	1782.07	**8.28**
5	Agriculture	930671	13639.59	80509	1553.37	**11.39**
6	MUDRA	512962	4687.73	43202	460.01	**9.81**
7	Stand-up India	9316	215.27	208	31.66	**14.71**

(Source : REVAMP Portal)

बैंकों में एन.पी.ए. की स्थिति चिन्ताजनक है तथा बैंकिंग को संपोषणीय (sustainable) बनाने हेतु समस्त सम्बन्धित बिभागों से आग्रह है कि वे बैंक के एन.पी.ए. खातों में वसूली हेतु बैंकों का सहयोग एवं सार्थक प्रयास करें, जिससे कि बैंक षाखायें सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं में ऋण वितरण हेतु उत्साहित हों।

- बैंक स्थानीय स्तर पर प्रषासन से समन्वय स्थापित करते हुये बैंक के एन.पी.ए. कम करने का प्रयास करें।
- बैंक तहसील से आर.सी. का मिलान करें तथा ऋण राषि की वसूली हेतु अमीनों का सहयोग प्राप्त करें।

(ख) लम्बित वसूली प्रमाण पत्र (R.C.) :

Progress as on 31.03.2023 **(Amt. in Cr.)**

Sr.	District	RCs Pending								Total RCs Pending		Recovery agt. RC 01.04.22 to 31.03.23		% Recovery agt. RC lodged
		Less than 1 Year		1 to 3 Years		3 to 5 Years		More than 5 Years						
		No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	
1	Uttarkashi	631	2.66	189	0.69	69	0.18	16	0.02	905	3.55	472	2.90	81
2	New tehri	2499	33.57	347	3.62	282	2.82	263	2.22	3391	42.23	168	4.70	11
3	Pauri	670	6.29	710	4.20	67	0.98	52	0.28	1499	11.73	118	1.03	9
4	Chamoli	152	0.75	353	1.69	144	0.87	97	1.41	746	4.72	92	0.28	6
5	Pithoragarh	610	3.68	785	5.85	642	2.73	0	0	2037	12.26	162	1.69	14
6	Rudraprayag	273	1.66	191	1.07	86	0.22	23	5.71	573	3.01	161	2.73	91
7	Bageshwar	194	1.49	15	2.00	0	0	0	0	209	1.51	98	1.19	79
8	Champawat	217	1.70	199	1.26	316	1.40	114	0.43	846	4.79	301	1.49	31
9	Almora	952	6.62	373	4.07	147	1.13	103	0.36	1575	12.19	105	0.90	7
10	Dehradun	3494	60.63	937	13.33	1013	12.86	0	0	5444	86.82	1376	11.56	13
11	Haridwar	576	0.45	826	7.30	413	3.65	310	1.19	2125	12.6	576	7.95	63
12	Nainital	176	2.79	184	1.40	23	0.31	0	0	383	4.50	90	0.90	20
13	U.S.Nagar	458	2.73	448	2.35	102	1.84	0	0	1008	6.92	263	5.46	79
Total		**10902**	**125.02**	**5557**	**48.83**	**3304**	**28.99**	**978**	**11.62**	**20741**	**206.83**	**3982**	**42.78**	**13**

(Source : CRA of District)

- बैंक तहसील दिवस में भागीदारी करें तथा अपने बैंक की आर.सी. से सम्बन्धित विषय पर ए.डी.एम., वित्त एवं तहसीलदार से चर्चा करें। उक्त बैठक में अमीनों को भी आमंत्रित किया जाता है।
- बी.एल.बी.सी. बैठक में अनिवार्य रुप से नायब तहसीलदार को भी आमंत्रित किया जाय तथा आर.सी. में वसूली हेतु सहयोग की अपेक्षा की जाय।
- बैंकों से आग्रह है कि वे ऑनलाईन दर्ज की गयी आर.सी. का मिलान तहसील से अवष्य करें।
- षासन से आग्रह है कि आर. सी. अंतर्गत वसूल राषि को पोर्टल में दर्ज कराने की व्यवस्था करें।

एजेण्डा संख्या – 7 :

(i) वित्तीय समावेषन :

NSFI के मुख्य कार्यबिन्दु निम्न हैं :

(क) बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एवं कैपेसिटी बिल्डिंग :

Business Correspondent विषयक प्रगति निम्नवत है : **(Annex. – 16)**

		Total No. of B.C..	Active B.C.	In-Active B.C.	No. of B.C. completed B.C. Certification Course	No. of remaining B.C. for completion of B.C. Certification Course
As on 31.03.23	Bank	4502	3979	499	3050	1452
	IPPB	163	69	94	51	112
As on 31.03.22	Bank	3686	3317	369	2258	1428

- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा Liability led Business Model के अंतर्गत कार्य करने वाले सी.एस.पी. की संख्या अपनी रिपोर्ट में प्रदर्षित की जाती है।
- वित्तीय वर्ष 2022–23 में 843 बी.सी. द्वारा B.C. Certification Course पूर्ण किया गया है।
- CSC e-governance से जानकारी वांछित है कि उनके कितने बी.सी. द्वारा बी.सी. सर्टिफिकेषन कोर्स पूर्ण किया गया है।

CSC e-governance की बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट विषयक प्रगति, दिनांक 30.06.2023 :

Sr.	Bank Name	Total BC	Active BC	In-Active BC	IIBF Course completed by (No. of BC)
1	SBI	103	99	4	101
2	PNB	27	25	2	24
3	HDFC	178	134	44	87
4	Axis	631	396	235	328
5	BOI	21	21	0	17
6	BOB	122	117	5	103
Total		**1082**	**792**	**290**	**660**

(ख) बैंकिंग सुविधा से अनाच्छादित गांव :

वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 17.03.2023 की संलग्न सूची में उत्तराखण्ड राज्य में जन धन दर्षक ऐप के अनुसार निम्नांकित 05 गांवों को बैंकिंग सुविधा से अनाच्छादित दिखाया गया है :

District Name	Sub District Name	Village Code	Village Name	Total Population	Allocated Bank	Remarks
Bageshwar	Kapkot	050517	Bor Balra	324	IPPB	Covered by IPPB
Pithoragarh	Dharchula	049086	Kuti	363	SBI	Covered by SBI BC
Pithoragarh	Dharchula	049073	Sipu	136	SBI	Covered by SBI BC
Rudraprayag	Ukhimath	042054	Garuriya	10	SBI	In Process
Uttarakashi	Rajgarhi	040285	Jakhali	82	IPPB	Covered by IPPB

- बैंकिंग सुविधा से अनाच्छादित उपरोक्त 05 गांवों में से 04 गांव आच्छादित कर दिये गये हैं तथा षेष 01 गांव (ग्राम गरुरिया, जिला रुद्रप्रयाग) को आच्छादित करने की प्रक्रिया प्रगतिषील है।
- IPPB से आग्रह है कि आच्छादित गांव Bor Balra एवं Jakhali को जन–धन दर्षक ऐप में अपडेट करें।

Status of 103 unbanked villages in State :

अन्तर राज्य परिषद, सचिवालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की प्रस्तावित 24वीं बैठक दिनांक 15.07.2023 को नरेन्द्र नगर में आयोजित की जा रही है, जिसमें अनाच्छादित 103 गांवों विषयक एजेण्डा है, जिन्हे जिला सहकारी बैंक एवं आई.पी.पी. बी. द्वारा आच्छादित किया जाना है। उक्त विषयक सूचना निम्नानुसार उत्तराखंड षासन को प्रेषित की गयी है :

Sr.	Particulars	No. of Villages
1	Uncovered villages as per list received from Inter State Council Secretriat	103
2	Number of villages covered by IPPB	25
3	Number of villages covered by District Co-operative Bank	10
4	Number of villages covered commonly by IPPB and District Co-operative Bank	12
5	Total Number of Villages covered (2+3+4)	47
6	Number of villages remained uncovered	56

Remarks for remaining uncovered 56 villages

Sr.	Particulars	No. of Villages
1	Proposed branch of DCB at Gandikhata, Distt. Haridwar, permission awaited from RBI	01
2	India Post Payment Bank (IPPB) is in process and will be covered by Dec., 2023	11
3	Difficulties being faced by District Co-operative Bank and India Post Payment Bank	44
	i) Seasonal / Migration villages	
	ii) No proper road connectivity	
	iii) No internet connectivity	
	iv) No electricity in 17 villages	

उपरोक्तानुसार अनाच्छादित 103 गांवों में से 17 गांवों में विद्युत नही है, इस विषयक उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेषन लि., देहरादून द्वारा निम्नवत अवगत कराया गया है :

- 10 गांवों का विद्युतिकरण Migratory village / No connectivity by road / Heavy snow fall area / Estimated cost high के कारणों से नही किया गया है।
- अवशेष 07 गांवों का ग्रिड द्वारा विद्युतिकरण Forest issue / Estimated cost high / No connectivity by road / To provide connections to SSB, line construction is under progress. After completion of this line work all these villages will be electrified through grid which will take approximate 6 to 8 months के कारणों से नही हुआ है।

उपरोक्तानुसार अनाच्छादित 103 गांवों में से 40 गांवों में टेलीफोन कनेक्टीविटी नही है, इस विषयक दूरसंचार विभाग, देहरादून द्वारा निम्नवत अवगत कराया गया है :

- Out of 40 villages, 37 villages are already included in ongoing USOF's (Universal Service Obligation Fund) 4G Saturation Scheme which is being implemented by BSNL.
- Out of rest 3 villages, there is 4G signal of RJIL in 2 villages (Mosta and Ahamadpur Chiriya) – same has also been confirmed from Village Secretaries/Gram Pradhans of the villages. Remaining village Bakora in Block Champawat is partially covered with RJIL signal, however for better connectivity and seamless 4G coverage, this village will be sent to USOF for inclusion in the current 4G saturation scheme.

(ग) सामाजिक सुरक्षा योजना :

वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देषानुसार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (पी.एम.जे.डी.वाई., पी. एम.एस.बी.वाई. एवं पी.एम.जे.जे.बी.वाई.) अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक खाताधारकों को योजना अंतर्गत आच्छादित किया जाय।

योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए बैंकों द्वारा दिनांक 31.03.23 तक निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी है :

(Annex. – 17)

योजना	आच्छादित खातों की संख्या		Increase	Increase %
	As on 31.03.22	As on 31.03.23		
पी.एम.जे.डी.वाई खाता संख्या (PMJDY)	30,39,442	33,83,578	3,44,136	11.32
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)	22,62,442	28,78,478	6,16,036	27.23
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)	5,58,148	8,29,556	2,71,408	48.63
अटल पेंषन योजना (APY)	3,93,453	5,87,787	1,94,334	49.39

(**Source** : F.I. Plan Portal - PMJDY, Banks - PMSBY, PMJJBY, PFRDA , PFRDA - APY)

पी.एम.जे.डी.वाई. खातों की संख्या F.I. Plan Portal से तथा पी.एम.एस.बी.वाई., पी.एम.जे.जे.बी.वाई. के आंकड़े बैंकों से एवं ए.पी.वाई. के आंकड़े PFRDA से प्राप्त किये गये हैं। उपरोक्त आंकड़ों में पी.एम.जे.डी.वाई. खाताधारकों के अतिरिक्त अन्य खाताधारकों के आंकड़े भी पी.एम.एस.बी.वाई. एवं पी.एम.जे.जे.बी.वाई. योजना अंतर्गत सम्लित हैं।

(घ) जन सुरक्षा योजनाओं हेतु संतृप्तता अभियान :
(दिनांक 01.04.2023 से 30.06.2023 तक)

संतृप्तता अभियान दिनांक 31.07.2023 तक बढ़ा दिया गया है।

वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.04.2023 से 30.06.2023 तक प्रधानमंत्री जीवन–ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) अंतर्गत संतृप्तता हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर कैम्प आयोजित किये गये हैं। योजना अंतर्गत ग्राम स्तर पर अधिक से अधिक ग्रामीणों, प्रधानमंत्री आवास योजना (षहरी एवं ग्रामीण) के लाभार्थी, मनरेगा कर्मचारी, एस.एच.जी के सदस्य, पी.एम.किसान सम्मान निधि के लाभार्थी तथा अन्य लोगों को योजना अंतर्गत संतृप्त किया गया है।

जन सुरक्षा योजनाओं हेतु संतृप्तता अभियान अंतर्गत दर्ज प्रगति निम्नवत है :

Active Enrolment (PMJJBY)	Active Enrolment (PMSBY)	Total No. of GPs	No. of GPs covered	GPs cover %	PMJJBY Sourced	PMJJBY Opened	PMSBY Sourced	PMSBY Opened
7,16,353	25,44,229	7,791	6,682	86	1,05,611	63,604	2,29,735	1,52,211

PMJJBY			PMSBY		
Active Enrolments Target	Active Enrolments	Active Enrolments %	Active Enrolments Target.	Active Enrolments	Active Enrolments %
10,90,000	7,16,353	66	31,67,000	25,44,229	80

Financial Inclusion Data as on 31.03.2023 :

Sr.	Particulars	As on 31.03.22	As on 31.03.23	Increase	Increase %
1	PMJDY A/c	30,39,445	33,83,578	3,44,133	11.32
2	Zero Balance A/c	1,90,120	2,30,043	39,923	21.00
2	Rupay Card Issued	20,93,177	22,41,129	1,47,952	7.07
3	% of Rupay Card	68.87	66.24	42.99	---
4	Aadhar Seeded	23,88,246	27,11,098	3,22,852	13.52
5	% of Aadhar Seeding	78.58	80.13	93.82	---

(Source : FI Plan Portal)

(ङ) वित्तीय साक्षरता हेतु केन्द्र (CFL) :

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित वित्तीय समावेषन के लिए राष्ट्रीय नीति (NSFI) 2019–2024 के अंतर्गत प्रथम फेज में राज्य के समस्त जिलों के 16 ब्लाकों में प्रायोजक बैंकों (भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेषनल बैंक एवं बैंक ऑफ बड़ौदा) के सहयोग से CRISIL Foundation (implementing NGO) द्वारा वित्तीय साक्षरता केन्द्र की स्थापना की गयी हैं।

Major Highlights of the CFL Project in the State :

- In Phase-I, 16 CFL have been opened in 16 Blocks. Reimbursement of 90% Opex and 100% Capex will be done by RBI.
- In Phase-II, 16 CFL have been opened in 16 Blocks. Reimbursement of 90% Opex and 100% Capex will be done by NABARD.
- In our State, three Sponsor Banks namely State Bank of India (SBI), Punjab National Bank (PNB) and Bank of Baroda (BoB) have been given the responsibility for CFLs in the State.

(च) वित्तीय साक्षरता केन्द्र (FLC) :

राज्य में 16 वित्तीय साक्षरता केन्द्र कार्यरत हैं, जिनकी मार्च, 2023 त्रैमास की प्रगति रिपोर्ट निम्नवत है :

Sr. No.	District	FLC Trainer	Name of Sponsoring Bank	FLC Manager				Rural Branches	
				No. of Sepcial Camps	participa nt	No. of specific Camps	Participants	Camps	
1	Uttarkashi	LDM	SBI	6	127	16	404		237
2	New Tehri	FLC	SBI	12	306	27	599		282
3	Chamoli	LDM	SBI	6	144	17	388		132
4	Champawat	FLC	SBI	7	223	13	388		437
5	Bageshwar	FLC	SBI	7	242	27	740		171
6	Pithoragarh	LDM	SBI	6	149	20	465		251
7	Rudraprayag	FLC	SBI	6	177	16	505		117
8	Pauri	FLC	SBI	10	169	15	240		394
9	Almora	FLC	SBI	6	240	15	483		149
10	Dehradun	Hired Trainer	PNB	6	217	22	1532		122
11	Haridwar	Hired Trainer	PNB	6	239	15	404		185
12	Nainital	Hired Trainer	BOB	9	229	24	595		210
13	US Nagar	Hired Trainer	BOB	6	172	20	462		445
14	Tehri	Hired Trainer	UGB	7	87	11	109	Rural Camps	**3132**
15	Nainital	Hired Trainer	UGB	6	415	15	380	Special Camps	112
16	US Nagar	Hired Trainer	UGB	6	244	7	222	Specific Camps	280
	TOTAL			**112**	**3380**	**280**	**7916**	**Total Camps**	**3524**

- वित्तीय साक्षरता केन्द्रों द्वारा मार्च, 2023 त्रैमास में 3524 कैम्पों का आयोजन वित्तीय साक्षरता हेतु किया गया है, जिसमें **11296** प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया है।

(ii) (a) Fintech Absorption :

- फिनटेक भारत में वित्तीय समावेषन को बढ़ावा दे रहा है। जैसे–जैसे यह क्षेत्र विकसित और परिपक्व होता जा रहा है, इससे वित्त को अधिक सुलभ, नवीन और समावेषी बनाने की उम्मीद है।
- Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) के अनुसार वर्तमान में भारत में 2000 से अधिक फिनटेक स्टार्ट–अप हैं।
- उत्तराखण्ड राज्य में 152 फिनटेक कार्यरत हैं।
- फिनटेक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति वित्तीय संस्थानों, स्टार्ट–अप, सरकारी निकायों, उद्यम निवेषकों एवं नियामकों के बीच सहयोग का फल है। भारत का डिजीटल इंफ्रास्ट्रक्चर – जिसमें India Stack, Central KYC, Record Registry, Information Utilities आदि षामिल है।
- फिनटेक ने बैंकों के ग्राहकों को डिजीटल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु सक्षम बनाया है, बैंक षाखाओं में भौतिक यात्राओं की आवष्यकता को कम किया है और बैंकों एवं ग्राहकों दोनो के लिए लागत बचत की ओर अग्रसर किया है।

Fintech Data F.Y. 2022-23 :

(Value in Cr.)

Month	AePS		UPI		IMPS	
	Volume	Value	Volume	Value	Volume	Value
April, 22	25,31,838	273.20	5,02,39,206	7,907.49	39,99,226	2,464.10
May, 22	23,97,471	254.26	5,37,07,827	8,223.16	41,25,254	2,476.90
June, 22	25,53,779	265.38	5,12,74,069	7,982.86	37,57,735	2,376.57
July, 22	24,89,665	266.61	5,53,33,053	8,388.61	36,62,843	2,336.75
Aug., 22	26,16,569	276.70	5,81,39,612	8,415.33	36,45,670	2,347.97
Sept., 22	23,27,803	232.73	6,01,62,669	8,773.10	35,30,851	2,349.38
Oct., 22	28,34,329	313.69	6,60,02,030	9,899.16	37,82,997	2,542.56
Nov., 22	23,58,569	254.28	6,53,97,505	9,648.34	36,15,479	2,512.71
Dec., 22	23,08,717	241.82	6,86,78,710	10,146.77	36,86,637	2,627.97
Jan., 23	24,67,859	257.20	7,04,00,985	10,194.44	35,72,418	2,519.16
Feb., 23	22,72,944	239.26	6,65,06,645	9,851.39	30,44,721	2,302.51
Mar., 23	27,81,953	267.31	7,77,52,564	11,037.62	35,29,379	2,723.87
Total	**2,99,41,496**	**3,142.44**	**74,35,94,875**	**1,10,468.27**	**4,39,53,210**	**29,580.44**

(Source : NPCI)

RUPAY

(Value in Cr.)

Month	DEBIT		PREPAID		CREDIT	
	Volume	Value	Volume	Value	Volume	Value
April, 22	12,08,236	192.34	20,343	2.24	41,554	9.00
May, 22	12,35,165	199.51	13,513	1.49	46,462	10.06
June, 22	11,64,073	186.13	6,266	0.63	46,080	9.93
July, 22	11,36,535	176.63	6,689	0.61	46,062	10.11
Aug., 22	10,84,519	176.59	7,876	0.78	49,708	10.76
Sept., 22	10,05,998	166.72	7,819	0.83	49,560	11.17
Oct., 22	10,81,258	200.21	9,191	1.44	59,659	14.93
Nov., 22	9,72,894	169.60	8,431	1.52	58,223	13.83
Dec., 22	9,99,438	162.16	7,158	0.72	65,989	15.41
Jan., 23	9,01,007	157.58	6,106	0.46	68,070	16.27
Feb., 23	8,19,821	146.57	5,107	0.42	65,791	16.13
Mar., 23	8,65,798	145.77	5,846	0.42	74,151	18.36
Total	**1,24,74,742**	**2,079.82**	**1,04,345**	**11.49**	**6,71,299**	**155.98**

(Source : NPCI)

Summary

(Value in Cr.)

		Volume	Value
AePS		2,99,41,496	3,142.44
UPI		74,35,94,875	1,10,468.28
IMPS		4,39,53,210	29,580.45
RUPAY	DEBIT	1,24,74,742	2,079.82
	PREPAID	1,04,345	11.49
	CREDIT	6,71,299	155.98

(Source : NPCI)

(b) Agri-Fintech :

- एग्री–फिनटेक स्टार्टअप एफपीओ और किसानों की अर्थव्यवस्था में सुधार करके कृषि मूल्य श्रृंखला में अंतर को पाट रहे हैं।
- खेती और उधार देने की पारंपरिक प्रथाओं के विपरीत, यह एक पारदर्षी, समान और प्रौद्योगिकी समर्थित प्रणाली है, जो किसानों के लिए चीजों को सरल बनाती है। यह किसानो/एफपीओ के विकास की वकालत करता है, जिससे फलते–फूलते बाजार का मार्ग प्रषस्त होता है।
- कृषि फिनटेक को बैंकों, वित्तीय संस्थानों और मूल्य श्रृंखला संचालकों के बीच अंतराल को भरने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने, कृषि आदानों, कृषि स्वास्थ्य, जलवायु, उपज दर और कृषि अर्थव्यवस्था बनाने वाले बाजार मूल्यों के बीच अंतर को भरने के रुप में परिभाषित किया जा सकता है।
- एक व्यवहारिक समाधान के रुप में स्टार्टअप परिदृष्य के इस पहलू का उद्देष्य उत्पादकों, प्रोसेसर, एग्रीगेटर्स और व्यापारियों के बीच कुषल अंतर सम्बन्ध स्थापित करता है, जो अंततः खेती की प्रक्रिया को व्यवस्थित करता है।
- किसानों को उनके उत्पाद, इसकी उपज और न्यूनतम निवेष के साथ अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए इसे बेहतर बनाने की तकनीक के बारे में षिक्षित करने में भी निवेष किया जाता है।
- एग्री–फिनटेक स्टार्टअप किसानों/एफपीओ को कम कीमतों पर बेचने के दबाव से बचाने के लिए उच्च गुणवता वाले उत्पाद बोर्डो के महत्व पर जोर देते है। उनका लक्ष्य किसानों की आपूर्ति के लिए सबसे लाभदायक कीमतों को सुरक्षित करना है।

(iii) Depositors Education and Awareness (DEA) :

दिनांक 18 अप्रैल, 2023 को आयोजित 33rd Depositors Education and Awareness Fund Committee की बैठक में समिति द्वारा निर्देषित किया गया था कि समस्त बैंक अपने स्टाफ सदस्यों को मृत जमाकर्ताओं के नामांकित व्यक्ति/वैधानिक उत्तराधिकारी के साथ जमाकर्ताओं के खातों के निपटान विषयक sensitize करें।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45ZA के तहत बैंकिंग कम्पनी द्वारा एक या अधिक व्यक्तियों के खाते में जमा राषि रखी जाती है, तो जमाकर्ता एक व्यक्ति को नामांकित कर सकते है, जिसे जमाकर्ता या जमाकर्ताओं की मृत्यु की स्थिति में जमा राषि का भुगतान किया जा सकता है।

एजेण्डा संख्या – 8 :

ऋण जमा अनुपात (C.D. Ratio) :

राज्य का ऋण जमा अनुपात (C.D. Ratio) **54 %** है।

(Amt. in Cr.)

Sr.	COMPONENTS	As on 31.03.20	As on 31.03.21	As on 31.03.22	As on 31.03.23
1	Advances from Banks (Within State)	62397.00	66466.00	72958	85563
2	Advances from Banks (utilized in the state but sanctioned from outside the State)	10501.00	10758.00	9929	9869
3	RIDF	7393.00	7920.00	8507	9123
4	Total Advance (1+2+3)	80291.00	85143.00	91394	104555
5	Total Deposits	141234.00	159856.00	176555	194013
Credit Deposit Ratio (CDR) in Uttarakhand		**57%**	**53%**	**52%**	**54%**

. समस्त बैंकों से आग्रह है कि वे त्रैमास अंतराल पर outside finance के डाटा एस.एल.बी.सी. को प्रेषित करें।

जिलेवार ऋण जमा अनुपात (C.D. Ratio) निम्नवत है :

(Rs. in Cr.)

Sr.	District	No. of Branch	FY 2019-20	FY 2020-21			FY 2021-22			FY 2022-23		
			C.D. Ratio%	Total Deposite	Total Advances	C.D. Ratio %	Total Deposite	Total Advances	C.D. Ratio %	Total Deposite	Total Advances	C.D. Ratio %
1	**Dehradun**	582	41	64178	24215	**38**	**72179**	**25330**	**35**	**80434**	**29624**	**37**
2	Uttarkashi	69	42	2578	1123	44	2459	1276	52	2723	1358	50
3	Hardwar	288	79	22416	16875	75	24313	16076	66	26630	18189	68
4	**Tehri**	145	26	5845	1820	**31**	**5958**	**1928**	**32**	**6624**	**2354**	**36**
5	**Pauri**	207	24	10038	2458	**24**	**10159**	**2682**	**26**	**10684**	**2891**	**27**
6	Chamoli	101	75	3847	2731	**71**	4112	2883	70	4552	2899	64
7	**Rudra Prayag**	54	23	2195	545	**25**	**2284**	**643**	**28**	**2578**	**759**	**29**
8	**Almora**	152	23	6185	1459	**24**	**7120**	**1858**	**26**	**7612**	**2017**	**26**
9	**Bageshwar**	56	27	2002	520	**26**	**2185**	**575**	**26**	**2318**	**545**	**24**
10	Pithoragarh	109	43	4840	2026	**42**	5167	2350	45	5388	2339	43
11	**Champawat**	65	27	2506	732	**29**	**2669**	**894**	**34**	**2793**	**984**	**35**
12	Nainital	264	43	17553	7352	42	**20393**	**5364**	**41**	22403	11492	51
13	U S Nagar	344	113	15674	15370	98	17556	18028	103	19276	19980	104

- राज्य में ऋण–जमा अनुपात बढ़ाये जाने हेतु सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड षासन की अध्यक्षता में दिनांक 12.06.2023 को गठित समिति की बैठक आयोजित की गयी थी, जिसमें सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा निम्नवत अवगत कराया गया :

  – राज्य में big ticket size के कृषि एवं एम.एस.एम.ई. ऋण प्रदान करने से ऋण–जमा अनुपात बढ़ाया जा सकता है।

– ऋण–जमा अनुपात बढ़ाये जाने हेतु गठित DCC/Special Sub-Committee की बैठक नियमित अंतराल पर आयोजित की जाय तथा बैठक में जिले के eco system में बदलाव पर चर्चा की जाय तथा उसी के अनुरुप जिले का District Credit Plan तैयार किया जाय।

– कृषि क्षेत्र में AIF, National Live Stock Mission आदि योजनाओं के big ticket size ऋण प्रदान किये जांय।

– पी.एम.ई.जी.पी. योजना अंतर्गत रु. 50.00 लाख तक के ऋण पर मार्जिन मनी सब्सीडी प्राप्त होती है तथा renewal with enhancement भी किया जा सकता है।

एजेण्डा संख्या – 9 :

ऋण आवेदन पत्रों के Rejected / Returned के कारण :

Scheme		No. of Applications Rejected / Returned	Reason
AIF		75	- Scheme is for advances to primary processing unit. - Individual applying for activities meant for SHG, FPO, SHG Fedration, FPO Fedration. - Banks rejecting applications for grading, shorting, packaging for apples. - PMU in State not yet activated.
PMFME		239	- Branches rejecting applications for clearences required post sanctioned - F.S.S.A.I. Certification. - Udyam Registration. - Collateral Security for loan application of Rs. 10 lacs. - GST Registration - Property already mortgaged for some other loan
PM SVANidhi	1st Tranche	5497	- Vendor Closed. - Out of City. - Aadhar not linked. - Having Mudra Loan.
	2nd Tranche	2227	- Vendor Closed . - High Interest Rate. - Not Interested. - Out of City.
MSY / PMEGP			- Low CIBIL Score - Applicant not wiling to avail loan - Required documents not provided to Banks - Not contactable - Out of service area - Not viable - Not a green field activity - Applicant in regular appointment

(Source : SLBC)

एजेण्डा संख्या – 10 :

(क) एम.एस.एम.ई. :

एम.एस.एम.ई. सेक्टर में बिगत 3 वर्षो की ऋण उपलब्धि :

(Amt. in Cr.)

F.Y.	MSME		
	Target	**Achievement**	**Achievement %**
2022-23	11994.00	15911.00	**133**
2021-22	10454.00	10055.00	**96**
2020-21	8851.00	8624.00	**97**

(Source : SLBC Revamp Portal)

वित्तीय वर्ष 2022–23 में निर्धारित लक्ष्य रु. 11994.00 करोड़ के सापेक्ष रु. 15911.00 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है, जो कि निर्धारित लक्ष्य का 133 प्रतिषत है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 की वार्षिक ऋण योजना में एम.एस.एम.ई. योजना अंतर्गत **रु. 11994.00** करोड़ में **रु. 4505.85 करोड़ (37.57%)** की बृद्वि कर वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु वार्षिक ऋण योजना एम.एस.एम.ई. योजना अंतर्गत **रु. 16500.00 करोड़** की गयी है।

एजेण्डा संख्या – 11 :

(क) मै. रुद्रा ऑटो टैक इंजीनियरिंग प्रा. लि. पंतनगर :
मै. नैनी ऑटो टैक रुद्रपुर यू.एस. नगर : प्रस्तुति – दि नैनीताल बैंक लि0

महानिदेषक/आयुक्त उद्योग, उद्योग निदेषालय, उत्तराखण्ड द्वारा पत्रांक 73–C/उ.नि./2023–24 दिनांक 11.04.2023 के माध्यम से निमनवत अवगत कराया गया है :

षासन से प्राप्त पत्र संख्या 224/ई–19111/VII-A-2/2023 दिनांक 23 मार्च, 2023 के साथ महामहिम राष्ट्रपति सचिवालय, (जनता II अनुभाग), राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली के पत्र संख्या Sl. No. p2/F/2002230057 दिनांक 20.02.2023 एवं पत्र संख्या Sl. No. p2/F/2002230062 दिनांक 20.02.2023 के संदर्भ में मै. रुद्रा ऑटो टैक इंजीनियरिंग प्रा. लि. पंतनगर एवं मै. नैनी ऑटो टैक रुद्रपुर यू.एस. नगर के प्रकरण को एस.एल.बी.सी. की बैठक में सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

प्रस्तुतीकरण – दि नैनीताल बैंक लि0

(ख) मै. गुरुकृपा इंटरप्राईजेज, ब्रहमपुरी, रुड़की : प्रस्तुति – पंजाब नेषनल बैंक

महानिदेषक/आयुक्त उद्योग, उद्योग निदेषालय, उत्तराखण्ड द्वारा पत्रांक 73–C/उ.नि./2023–24 दिनांक 11.04.2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उपरोक्त प्रकरण को एस.एल.बी.सी. की बैठक में सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

प्रस्तुतीकरण – पंजाब नेषनल बैंक

एजेण्डा संख्या – 12 :

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा।